>

Title: Need to enhance the financial package for Bundelkhand and also to take steps for development of this region of Madhya Pradesh.

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): अध्यक्ष महोदया, देश के पिछड़े हुए जिले हैं, उनमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छह जिले आते हैं। बुंदेलखंड का सागर क्षेत्र आपने देखा है। जैसा मैंने कहा कि बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके लिए वहां के जनप्रतिनिधियों ने लम्बा संघर्ष किया है और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बुंदेलखंड पिछड़ा जिला है। भारत सरकार ने तीन साल पहले बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की और लगभग सात हजार करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए देने का निर्णय किया। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए राज्य सरकार ने तेजी से विकास का कार्य किया।

महोदया, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव हुए और जो यूपी का बुंदेलखंड है, वहां कांग्रेस को पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण जो बुंदेलखंड पैकेज है, जिसकी तीन वर्ष की अवधि इस वर्ष समाप्त हो गई है और अभी पूरी राशि भी खर्च नहीं हो पाई है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि बुंदेलखंड के लिए तीन वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा जिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सागर लोकसभा क्षेत्र बुंदेलखंड का संभागी मुख्यालय और संभागी मुख्यालय होने के नाते सागर के अंदर बहुत पुरानी एयर स्ट्रिप है, अगर इस एयर स्ट्रिप के स्थान पर हवाई अड्डा बना दिया जाता है, तो बुंदेलखंड के विकास में चूंकि यह संभागी मुख्यालय है, बहुत तेजी आएगी। अगर बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार उद्योगों के लिए कोई विशेष पैकेज देती है या करों में छूट देती है, तो बुंदेलखंड के अंदर उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे बुंदेलखंड का विकास बढ़ेगा।

महोदया, आप जानती हैं कि सागर मुख्यालय में सैंट्रल यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने दी है, डॉ. हरी सिंह गौर ने एक बड़ा विश्वविद्यालय वहां बनवाया था, अगर वहां आईआईएम, आईआईटी जैसे कोर्स प्रारम्भ किए जाएं, तो जो पिछड़ा बुंदेलखंड है, उसका विकास हो सकेगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला है, जो बुंदेलखंड के लिए लाइफ लाइन बन सकता है। केन-बेतवा परियोजना, जिसका डीपीआर तैयार हो गया है, देश की एकमात्र ऐसी परियोजना है, जिसे उत्तर प्रदेश के उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने समझौता करके डीपीआर तैयार किया था, परन्तु भारत सरकार ने केन-बेतवा नदी परियोजना रोक दी है। इस तरह से बुंदेलखंड के विकास के लिए जो आवश्यक है, सागर क्षेत्र में अगर रेल कोच फैक्टरी का कारखाना लगता है, तो हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड के विकास के लिए भारत सरकार कम से कम 25 हजार करोड़ रुपए की राशि का पैकेज दे। इससे बुंदेलखंड का समग्र विकास हो सकेगा।